ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 119-123

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

उत्तराखण्ड राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय समस्या एवं महाविद्यालयी छात्रों का दृष्टिकोण

जगमोहन सिंह नेगी

एसो0 प्रोफे0, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपश्वर, चमोली (उत्तराखण्ड) भारत

Received- 02.12. 2019, Revised- 05.12.2019, Accepted - 09.12.2019 E-mail: jms7negi@gmail.com

सारांश : **'समस्या एक मूल्य निष्ठ अवधारणा हैं। बाधा, कठिनाई या चुनौती को समस्या कहते हैं या ऐसी स्थिति जिसमें मानव सुलझाने का प्रयत्न करता है। एक को सुलझाने के उपरान्त दुसरी जो खड़ी हो जाय वी समस्या कहलाती है। समस्या मावन जीवन का अविभाज्य अंग है। मानव न कभी समस्याओं से पूर्ण मुक्त रहा है और न ही रहने की सम्भावना भविष्य में है। लेकिन इतना निश्चित है कि आधुनिक समय में विद्यमान संचार की क्रांति, शिक्षा के प्रति लोगों की जागरुकता, स्वंय के प्रति चेतना ने मानव को समस्याओं के प्रति संवेदनशील एवं सजग बना दिया है।**

कुंजी शब्द – समस्या, मूल्य निष्ठा, बाधा, कठिनाई, चुनौती, अविभाज्य, विद्यमान, संचार की क्रांति।

मानव समाज में संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक भिन्नतांए पायी जाती है, परन्तु भिन्न–भिन्न समाजों में इनका स्वरूप प्रकृति एवं गहनता अलग–अलग होती हैं, जो समाज जितना अधिक गत्यात्मक एवं परिवर्तनशील होगा, उसमें उतनी ही अधिक समस्याएं विद्यमान होगी। समाज का ताना–बाना इतना जटिल है कि इसकी एक इकाई में होने वाला परिवर्तन अन्य इकाईयों को भी प्रभावित करता है। इस परिवर्तन का स्वरूप क्या होगा एवं इसके प्रभाव क्या होंगे? यह समाज की प्रकृति पर निर्भर करता है। विभिन्न युगों में सामाजिक परिवर्तन की गति अलग–अलग रही है। इसलिए भिन्न–भिन्न समाजों में समस्याओं की प्रकृति एवं स्वरूप भी अलग–अलग रही है। उत्तराखण्ड राज्य की पूर्व में समस्या अलग राज्य निर्माण की रही, लेकिन जब अलग राज्य बना गया, तब इसके समग्र विकास की समस्या है, और उस विकास के मार्ग में आने वाली समस्याओं के निदान करने की प्रमुखता है।

वर्तमान समय में सामाजिक परिवर्तन अति तीव्र गति से हो रहा है। इसके तरह बदलते आधुनिक समाज के स्वरूप ने समस्याओं में बेतहाशा वृद्धि की है। मानव समाज इन समस्याओं का उन्मूलन करने के लिए सदैव प्रयासरत रहा है। वर्तमान समय में उत्तराखण्ड राज्य अनेक समस्याओं से पीड़ित है। जिनके निराकरण के लिए राज्य व यहां के लोगों द्वारा मिल कर प्रयास जारी हैं, लेकिन फिर भी यहां प्रमुख समस्याओं में बेरोजगारी, असमानता, अशिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य, पलायन, पेयजल, आर्थिक विकास, यातायात एवं संचार, जल, जंगल, जमीन पर स्थानीय हक–हकूक, पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों का विकास आदि बहुत समस्याएं हैं जिनको जानने की अभिरुचि एवं निराकरण करने की यहां के लोगों की प्रमुखता है। इन्हीं समस्याओं को मध्य नजर रखते हुए प्रस्तुत शोध कार्य का अध्ययन अपने आप में महत्वपूर्ण है। अध्ययन हेतु जनपद चमोली को अध्ययन क्षेत्र के रूप में लिया गया है तथा अध्ययन ईकाई के रूप में महाविद्यायल के युवा छात्रों का चयन किया गया है, क्योंकि समाज में यह वर्ग अन्य वर्गो की अपेक्षा सर्वाधिक शिक्षित होने के साथ–साथ ऊर्जावान भी है, जिस कारण वह समस्याओं को अच्छे से समझा सकता है और उनके निराकरण हेतु प्रभावी कदम उठा सकता है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय– जनपद चमोली उत्तराखण्ड का एक सीमान्त जनपद है। इसकी सीमा चीन एवं नेपाल देश से लगी हुई है। आजादी से पूर्व यह जनपद पौड़ी जनपद की एक तहसील मात्र था। लेकिन प्रशासनिक सुविधा एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र होने के कारण 24 फरवरी, 1960 को केन्द्रीय सरकार ने इसे अलग जनपद का दर्जा प्रदान किया। जनपद चमोली में हिमाच्छादित ऊंचे–ऊंचे पर्वत शिखर, उन पर सुशोभित हिमानियां और इन हिमानियों से झरते झरने, निकलती नदियां, नदियों से बनती घाटियां विश्व प्रसिद्ध हैं। यहां भगवान श्री बदरी नारायण, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, भविष्य बदरी, ध्यान, योग बदरी, आदि बदरी, हेमकुण्ड साहिब, मां अनसूया आदि शैव, वैष्णव एवं शाक्त सम्प्रदायों से सम्बन्धित विश्व प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल हैं। नन्दा देवी राज जात जैसी धार्मिक यात्राओं के अतिरिक्त फूलों की घाटी, विश्व प्रसिद्ध स्कीकिंग क्षेत्र औली, वेदनी बुग्याल आदि पर्यटन स्थल भी अवस्थित हैं, जिस कारण यह जनपद उत्तराखण्ड में ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण देश में तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों के लिए पूर्व समय से आकर्षण का केन्द्र है।

वर्तमान में जनपद चमोली कुल 9 विकासखण्डों से मिलकर बना हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 7626 वर्ग कि.मी. है तथा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 391114 है, जिसमें से 193572 पुरुष

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

तथा 197542 महिलाएं हैं। कुल साक्षरता 83.48 प्रतिशत है। जिनमें से 94.18 प्रतिशत पुरुष तथा 73.20 प्रतिशत महिलाएं हैं। कुल लिंगानुपात 1021/1000 है। उच्च शिक्षा के लिए जनपद में में 8 राजकीय महाविद्यालय तथा 6 मान्यता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालय हैं, जिनमें पर्याप्त मात्रा में जनपद तथा जनपद के बहार के छात्र/छात्राएं अध्यनरत् हैं।

अध्ययन के उद्देश्य–

1. महाविद्यालयी छात्रों की राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय समस्या के सम्बन्ध में दृष्टिकोण तथा छात्र एवं छात्राओं के तुलनात्मक दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
2. महाविद्यालयी छात्रों की स्थानीय समस्याओं के बारे में जानने की अभिरुचि एवं छात्र–छात्राओं की इस सम्बन्ध में पृथक्–पृथक् अभिरुचि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. महाविद्यायली छात्रों की स्थानीय समस्याओं के निराकरण का प्रभावी माध्यम के सम्बन्ध में दृष्टिकोण एवं छात्र–छात्राओं की इस सम्बन्ध में पृथक्–पृथक् अभिरुचि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना–

1. महाविद्यालयी छात्रों की राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय समस्या के सम्बन्ध में दृष्टिकोण एवं छात्र/छात्राओं के तुलनात्मक दृष्टिकोण में अन्तर है।
2. महाविद्यालयी छात्रों की स्थानीय समस्याओं के बारे में जानने की अभिरुचि एवं छात्र/छात्राओं की तुलनात्मक अभिरुचि में अन्तर है।
3. महाविद्यायली छात्रों की स्थानीय समस्याओं के निराकरण का प्रभावी माध्यम के सम्बन्ध में दृष्टिकोण एवं छात्र/छात्राओं के तुलनात्मक दृष्टिकोण में अन्तर है।

अनुसन्धान प्रविधि– प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु सामाजिक अनुसन्धान की वैज्ञानिक पद्धति को प्रयोग में लाया गया है। अध्ययन इकाई के चयन हेतु उत्तराखण्ड राज्य के सीमान्त जनपद चमोली में 15 महाविद्यालयों में से 06 महाविद्यालयों का लॉटरी पद्धति द्वारा चयन किया गया तथा प्रत्येक महाविद्यालय से 25 छात्र तथा 25 छात्राओं कुल मिलाकर 300 छात्र/छात्राओं का यादृच्छिक न्यादर्शन (देव निदर्शन) तकनीकी द्वारा साक्षात्कार के लिए चयन किया गया। साक्षात्कार अनुसूची द्वारा चयनित छात्र/छात्राओं का साक्षात्कार लिया गया और उनसे प्राप्त तथ्यों को प्रकाशित करने योग्य बनाने के लिए प्रतिशत विधि को प्रयोग में लाया गया है, जिससे स्पष्ट निष्कर्षों का प्रतिपादन किया गया है।

विश्लेषण, व्याख्या, परिणाम और सुझाव–

आधुनिक लोकतन्त्रात्मक राज्य में और खासकर आदिवासी व पिछड़े पर्वतीय भू–भागों में जहां सरकार विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर विकास के वाहक की भूमिका निभा रही है वहां विकास की गति यदि जनाकांक्षाओं के अनुरूप होती है तो समाज तथा राजनीतिक जीवन में सुस्थिरता रहती है। यदि विकास जन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होता है अथवा शासकीय कानून विकास के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं तो ये सारी बातें समस्या के रूप में जन समान्य के सम्मुख उत्पन्न हो जाती हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव जन सामान्य पर पड़ता है। इन समस्याओं में से कोई न कोई समस्या जन समान्य को विशेष रूप से प्रभावित करने लगती हैं।

छात्र या स्थानीय जनता इस प्रकार की प्रमुख समस्याओं के सम्बन्ध में निरन्तर जागरुक रहते हैं। उत्तराखण्ड राज्य की उल्लेखित प्रमुख समस्याओं के सम्बन्ध में प्रतिदर्श उत्तरादाताओं के दृष्टिकोण को जाने के प्रायास से उनसे शोध सर्वेक्षण साक्षात्कार के दौरान यह प्रश्न पूछा गया कि आपके राज्य की सबसे बड़ी समस्या क्या हैं। इस सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया को सारणी संख्या–01 में देखा जा सकता है।

सारणी संख्या –01

राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय समस्या के सम्बन्ध में छात्रों का दृष्टिकोण

उत्तरदाता	शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल		यातायात एवं संचार		बेरोजगारी		आर्थिक विकास		योग	
	संख्या	प्रतिषत	संख्या	प्रतिषत	संख्या	प्रतिषत	संख्या	प्रतिषत	संख्या	प्रतिषत
छात्र	14	09.33	13	8.67	74	49.33	49	32.67	150	100.00
छात्राएं	17	11.33	16	10.67	70	46.67	47	31.33	150	100.00
कुल योग	31	10.33	29	9.67	144	48.00	96	32.00	300	100.00

सारणी में उत्तरादाताओं द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की प्रमुख समस्या को उजागार किया गया है। कुल उत्तरदाताओं में से 48.00 प्रतिशत ने बेरोजगारी को यहां की प्रमुख समस्या बताया है, जबकि 32.00 प्रतिशत ने आर्थिक विकास को, 10.00 प्रतिशत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल को राज्य की प्रमुख समस्या माना है तथा 9.67 प्रतिशत ने यातायात एवं संचार को सबसे मुख्य समस्या माना है।

उत्तराखण्ड राज्य की प्रमुख समस्या के सम्बन्ध में छात्र–छात्राओं की प्रतिक्रिया का पृथक्–पृथक् अध्ययन करने से स्पष्ट है कि छात्र वर्ग में 49.33 प्रतिशत ने बेरोजगारी, 32.67 प्रतिशत आर्थिक विकास, 9.33 प्रतिशत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल तथा 8.67 ने यातायात व संचार को प्रमुख्य समस्या के रूप में माना है, जबकि छात्रा वर्ग में 46.67, 31.33, 11.33, 10.67 प्रतिशत छात्राओं ने क्रमशः बेरोजगारी, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य व पेयजल, यातायात व संचार को यहां की प्रमुख समस्या बताया है।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

अतः स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरादाताओं ने यहां की प्रमुख समस्या को बेरोजगारी बताया है। यद्यपि बेरोजगारी वर्तमान में मात्र उत्तराखण्ड राज्य की ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण देश की एक प्रमुख समस्या है, लेकिन उत्तराखण्ड राज्य के छात्र भी इससे अछूते नहीं हैं। राज्य गठन के बाद भी यहां के लगभग 50 प्रतिशत युवा रोजगार की तलाश में मैदानी भागों में पलायन करने पर मजबूर हैं।1 यही नहीं सराकर द्वारा रोजगार के अनेक कार्यक्रमों के संचालन के बावजूद भी लाखों शिक्षित बेरोजगार हैं,2 जो निरन्तर बदलते परिवेश ओर सरकारी नौकरियों में कमी के चलते रोजगार कार्यालयों से भी निराश हो गये हैं। यहां के युवा छात्रों की योग्यता एवं अपेक्षा के अनुकूल रोजगार या नियुक्ति नहीं हो पा रही है।

बेरोजगारी के साथ ही में 32 प्रतिशत छात्रों ने आर्थिक विकास को राज्य उत्तराखण्ड की प्रमुख समस्या बताया है। उत्तराखण्ड राज्य सामान्यतः आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है। छोटी जोत वाली कृषि योग्य भूमि ही इनकी परम्परागत आजीविका का आधार है। लेकिन आज भी लोग खेती में परम्परागत विधियों का प्रयोग करते हैं, जो अवैज्ञानिक होने के साथ–साथ कम उपजाऊ भी है। मवेशी पालन भी जनता का आर्थिक स्तर आंकने का महत्वपूर्ण मापदण्ड हैं। वर्तमान में अच्छी नस्ल के मवेशियों के विकास से जहां पशुधन देश में लाभदायक सिद्ध हो रहा है। वही आज भी उत्तराखण्ड में अच्छी नस्ल के पशु नहीं हैं।3 इसके साथ ही समूचा पर्वतीय क्षेत्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है।4 उत्तराखण्ड के 13 जनपदों में से नैनीताल और देहरादून में ही लघु व मध्यम उद्योग हैं।5 इस प्रकार उद्योगों की उपेक्षा ही नहीं, कच्चे माल का बहिगर्मन जनसंख्या की वृद्धि, बागवानी का अभाव, चारागहों एवं वनों का विनाश आदि जटिलताओं ने नवोदित राज्य के आर्थिक विकास को व्यापक रूप से प्रभावित कर रखा है। कुल 10.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेजयल की समस्या को राज्य की प्रमुख समस्या माना है। व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा के विकास के माध्यम से जहां पूरे देश में उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने पर बल दिया जा रहा है।6 वहीं उत्तराखण्ड राज्य में आजादी के बाद भी इस दिशा में वांछित प्रगति नहीं हो पायी है। यही नहीं उत्तराखण्ड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाओं की कमी वर्तमान में भी जस की तस बनी हुई है। कई स्थानों पर विद्यालय खोल तो गये हैं, लेकिन उनमें पर्याप्त संख्या में अध्यापकों का अभाव है। यही स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं की भी हैं। राज्य के कई स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधायें भी उपलब्ध नहीं है। यदि किसी क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र हैं, भी तो वहां डाक्टर, स्टाफ अथवा औषधियों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

विश्व प्रसिद्ध गंगा, यमुना, सरयू, रामगंगा अथवा भारत के उत्तरी मैदान को सिंचित व पेयजल की पूर्ति करने वाली सदानिरा नदियों का उद्‌गम स्थल राज्य उत्तराखण्ड है।7 फिर भी वाटर टैंक कहे जाने वाले राज्य के लोग पेयजल की समस्या से ग्रस्त हैं।8 कई प्राकृतिक एवं भौतिक परिवर्तनों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत जल स्रोतों के सूखने से यह समस्या और भी जटिल बलन गयी है। एक अनुमान के तहत लगभग 50 प्रतिशत से ज्यादा प्राकृतिक जल स्रोत सूख चुके हैं9 और जो शेष हैं वह बिना संरक्षण के अभाव में सूखने के कगार पर हैं। यही नहीं शहरी क्षेत्रों में बढ रही आबादी ने ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल पूर्ति में निरन्तर कमी कर दी है। शहरी क्षेत्रों में औसतन 4–5 घण्टा पीने के पानी की व्यवस्था है।

प्रतिदर्श उत्तरादाताओं में से कुल 9.67 प्रतिशत उत्तरादाताओं ने राज्य की मुख्य समस्या राज्य में यातायात व संचार विकास को बताया। अधिकांश गांव प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं की घोषणा के बावजूद भी मोटर यातायात मार्गों से आज तक भी नहीं जुड़ पाये हैं, यही स्थिति संचार व्यवस्था की भी है। यदि कही संचार व्यवस्था कायम भी है, तो लाईनों की स्थिति इस कदर है कि फोन मिलाने में उतना समय लग जाता है, जितने समय में उस स्थान पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। फलस्वरूप यातायात व संचार साधनों के अभाव के कारण यह क्षेत्र विकास के सभी सोपानों में अत्यधिक पिछड़ा हुआ है।

वस्तुतः स्थानीय समस्याओं का छात्रों पर भी गहन प्रभाव पड़ता है। अतः स्वाभाविक रूप से छात्र स्थानीय समस्याओं की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, लेकिन छात्रों में क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रवृत्ति बहुत कुछ विद्यमान परिवेश चेतना के स्तर, शिक्षा की गुणवत्ता, पारिवारिक संरचना, सामाजिक परम्पराओं और मूल्यों पर आधारित होती है, क्योंकि प्रत्येक छात्र में संस्कार और मूल्य या पारिवारिक परिवेश के लक्षण और सामाजिक–आर्थिक दृष्टिकोण विद्वमान रहता है। अतः समस्या की पृष्ठिभूमि व्यक्तिनिष्ठ होती है। यही कारण है कि अलग–अलग छात्रों का समस्याओं के प्रति अलग–अलग दृष्टिकोण होता है। कुछ अपने घर के परिवेश के सम्बन्ध में संवेदनशील होते हैं, तो कुछ महाविद्यालय के बारे में और कुछ राष्ट्रीय व राज्य परिवेश के सम्बन्ध में संवेदनशील होते हैं, जबकि कुछ छात्र अपने अध्ययन काल में अपने भविष्य के प्रति संवेदनशील होते हैं। कतिपय छात्र ऐसे भी होते हैं उनको उपरोक्त में से किसी भी क्षेत्र के प्रति कोई

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

अभिरुचि नहीं होती है। इस बात का परीक्षण करने और प्रतिदर्श उत्तरादाता छात्रों की स्थानीय समस्याओं के प्रति रुचि के सम्बन्ध में उनके दृष्टिकोण को जानने के लिए उनसे साक्षात्कार अनुसूची के माध्य से सर्वेक्षण के समय यह प्रश्न किया गया कि क्या आप स्थानीय समस्याओं को जानने में रुचि रखते हैं? अतः इस सम्बन्ध में उत्तरादाताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया का विश्लेषण सारणी संख्या–02 में किया गया है।

सारणी संख्या–02
स्थानीय समस्याओं के बारे में जानने की अभिरुचि

उत्तरादाता	सकारात्मक		नकारात्मक		योग	
	संख्या	प्रतिषत	संख्या	प्रतिषत	संख्या	प्रतिषत
छात्र	142	94.67	08	5.33	150	100.00
छात्राएं	139	92.67	07	7.33	150	100.00
कुल योग	281	93.67	15	6.33	300	100.00

अतः उक्त सारणी से स्पष्ट है कि अधिक छात्रों की स्थानीय समस्याओं के बारे में जानने की अभिरुचि सकारात्मक है, जबकि बहुत कम छात्रों की इस सम्बन्ध में अभिरुचि नकारात्मक है। साथ ही सारणी में यह भी स्पष्ट है कि छात्राओं की अपेक्षा छात्रों की अभिरुचि स्थानीय समस्याओं के बारे में जानने में अधिक सकारात्मक है। अतः उत्तरादाताओं की प्रतिक्रिया का समग्र रूप से अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता अपने क्षेत्र की समस्याओं से परिचित हैं अथवा प्रायः क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। यही नहीं उनके निराकरण करने हेतु भी रह स्तर पर प्रयासरत् रहते हैं।

किसी समस्या की प्रकृति के अनुरूप ही उसके निवारण का प्रयास किया जाता है। स्थानीय समस्याएं चूंकि क्षेत्र विशेष के सामाजिक सन्दर्भ के अन्तर्गत उभरती हैं। अतः स्वाभाविक रूप से ही उसी परिवेश से सम्बन्धित लोग उसके निकराकरण के प्रति प्रयत्नशील होते हैं। वस्तुतः सरकारी, गैर सरकारी स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक इन लोगों के सहयोग से समस्याओं का समाधान किया जाता है। स्थानीय समस्याओं के निराकरण के विभिन्न माध्यमों के अध्ययन हेतु शोधार्थी ने प्रतिदर्श उत्तरादाताओं से यह प्रश्न पूछा कि स्थानीय जनता में जागरुकता उत्पन्न करके, जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क करके, जिला प्रशासन के माध्यम से तथा सभी प्रकार के संयुक्त प्रयासों के माध्यम में से किस माध्यम के द्वारा स्थानीय समस्याओं का प्रभावी ढ़ंग से निराकरण किया जा सकता है। इस प्रश्न के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया सारणी संख्या–03 में दृष्टव्य है।

सारणी संख्या–03
स्थानीय समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में छात्रों का दृष्टिकोण

उत्तरदाता	जनता में जागरुकता उत्पन्न करके		जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क करके		जिला प्रशासन के माध्यम से		संयुक्त प्रयासों से		योग	
	संख्या	प्रतिषत	संख्या	प्रतिषत	संख्या	प्रतिषत	संख्या	प्रतिषत	संख्या	प्रतिषत
छात्र	61	48.67	11	7.33	2	1.33	76	50.67	150	100.00
छात्राएं	56	37.33	13	8.67	3	2.00	78	52.00	150	100.00
कुल योग	117	39.00	24	8.00	5	1.67	154	51.33	300	100.00

उपरोक्त सारणी में उल्लेखित आंकड़ों से स्पष्ट है कि स्थानीय समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में प्रतिदर्श उत्तरादाताओं के दृष्टिकोण में भिन्नता है। कुल 39 प्रतिशत का मानना है कि स्थानीय जनता में जागरुकता उत्पन्न करके ही स्थानीय समस्यओं का निराकरण किया जा सकता है। क्योंकि क्षेत्र विशेष की समस्याओं के निराकरण में स्थानीय जनता ही एकजुट होकर यथोचित संघर्ष कर सकती है तथा स्थानीय लोगों में जन चेतना उत्पन्न करके स्थानीय समस्याओं को आसानी से सुलझाया जा सकता है, जबकि 8 प्रतिशत ने बताया कि जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क कर के स्थानीय समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है, क्योंकि जन प्रतिनिधि जो कि जनता और शासन तन्त्र के मध्य सम्पर्क सूत्र का कार्य करता है, जिससे वह स्थानीय समस्याओं को शासन तक पहुंचा कर उसके निराकरण का उपाय सुझा सकता है, किन्तु मात्र 1.67 प्रतिशत उत्तरादाताओं का मानना है कि जिला प्रशासन के माध्यम से स्थानीय समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि जिला प्रशासन ही स्थानीय समस्याओं से अधिक परिचित रहता है और परिस्थितियों के अनुकूल विकास से जुड़े मुद्दों को सरकार से हल करने के साथ–साथ विकास योजनाओं को क्रियान्वित करके समाज को विकासोन्मुखी पर्यावरण प्रदान करता है, जबकि 51.33 प्रतिशत सभी प्रकार के संयुक्त प्रयासों से स्थानीय समस्याओं के निराकरण में विश्वास व्यक्त करते हैं।

इस सम्बन्ध में छात्र व छात्राओं के दृष्टिकोण का अध्ययन करने पर स्पष्ट है कि छात्राओं की अपेक्षा छात्र मानते हैं कि जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क करके, जिला प्रशासन के माध्यम से तथा संयुक्त प्रयासों से स्थानीय समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है, जबकि अधिकांश छात्र, छात्राओं की अपेक्षा यह स्वीकार करते हैं कि स्थानीय समस्याओं का निराकरण जनता में जागरुकता उत्पन्न करके ही किया जा सकता है। अतः उत्तराखण्ड राज्य के क्षेत्रीय विकास में कुछ समस्याएं अत्यधिक बाधक रही हैं। ऐसी समस्याओं में बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, यातायात, तथा संचार साधनों की कमी आदि प्रमुख है। इन सभी समस्याओं के कारण उत्तराखण्ड

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

राज्य के क्षेत्रीय विकास पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है।

अध्ययन में पाया गया है कि महाविद्यालयों में अधिकांश छात्र प्रमुख क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में जानकारी रखते हैं। सर्वक्षण में अधिकांश छात्रों ने बेरोजगारी को प्रमुख क्षेत्रीय समस्या बताया। छात्राओं की अपेक्षा छात्रों का दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में अधिक सकरात्मक रहा है तथा उनके निराकरण हेतु संयुक्त प्रयासों जैसे जनता में जागरुकता उत्पन्न करके जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क करके तथा जिला प्रशासन से सम्पर्क करके किया जा सकता है। साथ ही अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ है कि महाविद्यालयी छात्र स्थानीय समस्याओं को जानने की अभिरुचि रखते हैं। अर्थात् अधिकांश महाविद्यालयी छात्र अपने क्षेत्र की समस्याओं से परिचित हैं अथवा प्रायः क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इस सम्बन्ध में छात्रा वर्ग की अपेक्षा छात्रों का दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक पाया गया है। छात्रों की प्रमुख समस्या के समाधन हेतु यहां के पाठ्क्रमों को परिवर्तित किया जाया और इन पाठ्यक्रमों में सिद्धान्तिक शिक्षा की अपेक्षा व्यवहारिक रोजगार परक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किये जाने की आवश्यकता है। जिससे यहां का युवा वर्ग बेरोजगारी की समस्या से मुक्त हो सके। साथ ही अन्य समस्याओं का समाधन जल्दी–जल्दी खोजने में सफल हो सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. राम प्रसाद डोभालः उलझनों में फंसा उत्तरांचल, नगाधिराज त्रैमासिक पत्रिका, अखिल गढ़वाल सभा प्रकाशन देहरादून, 1 नवम्बर, 2002, पृ.सं. 43।
2. मुनि राम सकलानी : उत्तरांचल के विकास के लिए पलायन को रोकना होगा, यशवन्त सिंह कठोच द्वारा सम्पादित, उत्तराखण्ड संस्कृति, उत्तराखण्ड शोध संस्थान पौड़ी, 1 जनवरी, 2002, पृसं 11।
3. एन0पी0 टोडरिया : उत्तराखण्ड में महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति, शीला रावत द्वारा सम्पादित, उत्तराखण्ड दृष्टि, दशा और दिशा, शिवा ऑफसेट प्रेस, देहरादून, 1995, पृ.सं. 73।
4. आर0 एन0 गैरोला : उत्तराखण्ड की समस्याओं का समाधान उत्तराखण्ड राज्य , शीला रावत द्वारा सम्पादित, उत्तराखण्ड दृष्टि, दशा और दिशा, शिवा ऑफसेट प्रेस, देहरादून, 1995, पृ.सं. 95।
5. राम प्रसाद डोभालः उलझनों में फंसा उत्तरांचल, नगाधिराज त्रैमासिक पत्रिका, अखिल गढ़वाल सभा प्रकाशन देहरादून, 1 नवम्बर, 2002, पृ.सं. 43।
6. बी0के0 झा0 : व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा का राष्ट्रीय परिदृश्य, विश्वनाथ, द्वारा सम्पादित योजना, नई दिल्ली, सितम्बर, 2003, पृ.सं. 4
7. पी0आर0 शिल्पकारः गढवाल व कुमाऊं का उपेक्षित विकास, इलीइट प्रिंटर्स लखनऊ, 1993, पृ.सं. 4।
8. सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय उत्तरांचल : 21 वीं सदी में विकास की नयी बुनियाद, उत्तरांचल देहरादून, 2002, पृ.स.7।
9. नरसिंह यादवः भविष्य में बिकेंगे नदी और तालाब, सहारा समय, साप्ताहिक समाचार पत्र, नई दिल्ली 17 अप्रैल, 2004, पृ.सं. 35।

*****